

लेखक - नुशेबा इकबाल एवं हरीश दामोदरन ( संपादक )

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III

( भारतीय अर्थव्यवस्था ) से संबंधित है।

इंडियन एक्सप्रेस

15 जनवरी, 2020

“दिसंबर के लिए खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति छह साल के उच्च स्तर को छू गई है। इस आलेख में हम जानेंगे कि कीमतों के घटने की संभावना क्या है? इसके लिए जिम्मेदार कारक कौन-कौन से हैं? और सरकार इसके लिए क्या कदम उठा सकती है?”

सोमवार को राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने डेटा जारी किया, जिसके अनुसार दिसंबर के लिए वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) मुद्रास्फीति 7.35% थी, जो जुलाई 2014 के 7.39% के बाद से सबसे अधिक थी और साथ ही यह भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के ऊपरी लक्ष्य सीमा 6% से भी अधिक थी।

लेकिन सबसे बड़ा झटका तो खुदरा खाद्य मुद्रास्फीति ने दी, जो छह साल के उच्च स्तर यानी 14.12% से अधिक थी। यह देखते हुए कि खाद्य पदार्थों का समग्र सीपीआई में 45.86% हिस्सेदारी है, यह सवाल उठता है कि क्या वर्तमान उछाल क्षणभंगर है या ऐसे अन्य कारक हैं जो निकट भविष्य में कीमतों में गिरावट के रास्ते में आ सकते हैं।

खाद्य मुद्रास्फीति में उछाल कितना गंभीर है? क्या यह अपेक्षा से अधिक है?

उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (CPFI) सीपीएफआई मुद्रास्फीति में अचानक और तेज वृद्धि ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है। सितंबर 2016 से अगस्त 2019 तक विस्तारित अवधि के लिए साल-दर-साल सीपीएफआई मुद्रास्फीति लगातार समग्र सीपीआई मुद्रास्फीति से नीचे रही। लेकिन सीपीएफआई मुद्रास्फीति अगस्त में 2.99% से सितंबर में 5.11% हो गई, अक्टूबर में 7.88%, फिर नवंबर में 10.01% और दिसंबर में 14.12% हो गई। यह आखिरी आँकड़ा नवंबर 2013 के लिए 17.89% के बाद से सबसे अधिक था। दोनों में पहले गिरावट और बाद में वृद्धि हुई, जो सामान्य उपभोक्ता मुद्रास्फीति की तुलना में खाद्य पदार्थों के मामले में बहुत अधिक स्पष्ट है।

तो अचानक से आई इस उछाल के लिए कौन जिम्मेदार हैं?

इसका मुख्य कारण असमान बारिश होना है। इस साल दक्षिण-पश्चिम मानसून सीजन (जून-सितंबर) में जुलाई के आखिरी हफ्ते तक लगभग कम बारिश हुई। मॉनसून की शुरुआत देर से हुई और खरीफ की फसल की बुआई में देरी हुई। हालाँकि, सितंबर, अक्टूबर और यहाँ तक कि नवंबर की पहली छमाही में भारी बारिश हुई, जिससे फसल को नुकसान हुआ। अधिक और कम बारिश के कारण खरीफ फसलों के उत्पादन में व्यवधान कीमतों के बढ़ने का मुख्य कारण है, खासकर सितंबर से।

क्या यह उछाल अस्थायी है?

देखा जाए तो एक तरफ इसी बेमौसम बारिश ने खरीफ (मानसून) की फसल पर कहर बरपाया है, तो वहाँ दूसरी तरफ इसी बारिश ने भूजल को रिचार्ज करने में मदद की है और प्रमुख सिंचाई जलाशयों को उसकी पूरी क्षमता तक पहुँचा दिया है।

## भारत में मुद्रास्फीति की माप

### औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP)

- यह एक ऐसा सूचकांक है जो अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे-खनन, विद्युत, विनिर्माण आदि के लिए वृद्धि का विवरण प्रस्तुत करता है।
- इसमें 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त आँकड़ों के आधार पर आईआईपी का आकलन किया जाता है। इसमें औद्योगिक नीति एवं संबद्धन विभाग (डीआईपीपी), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और उर्वरक विभाग जैसे एजेंसियाँ शामिल हैं।
- इसे केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (CSO) द्वारा जारी किया जाता है, जो किसी चयनित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक बास्केट के उत्पादन की मात्रा में अल्पावधि में होने वाले परिवर्तनों का मापन करता है। इसका भी आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 को आधार वर्ष निश्चित किया गया है।

अब इस वजह से यह रबी (सर्दी-वसंत) की फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। सरकारी अँकड़ों से पता चलता है कि किसानों ने चालू रबी सीजन के दौरान 8% अधिक क्षेत्र बोया है। अधिक मिट्टी की नमी की स्थिति और एक सामान्य सर्दी के साथ, खरीफ के नुकसान की भरपाई के लिए अब उम्मीद की जा सकती है।

इसका एक उदाहरण प्याज हो सकता है। कृषि मंत्रालय ने 2019-20 में कुल उत्पादन का अनुमान खरीफ/देर-खरीफ के लिए 54.73 लाख टन पर लगाया है, जो कि पिछले साल के 69.91 लाख टन के इसी स्तर से लगभग 22% कम है। हालाँकि, रबी मौसम के दौरान रोपाई-जो भारत के प्याज उत्पादन का दो-तिहाई से अधिक है। किसानों द्वारा प्राप्त बेहतर जल उपलब्धता और उच्च मूल्यों के संयोजन के कारण 2018-19 में लगभग 19.5% अधिक है। यह फसल मार्च-अंत तक बाजार में उत्तरने लगेगी, जिससे कीमतों में कमी आने लगेगी।

यही बात कई अन्य संबिजियों पर भी लागू होती है, जिन्होंने संयोग से दिसंबर के लिए साल दर साल सीपीआई मुद्रास्फीति सबसे अधिक 60.5% दर्शाया है।

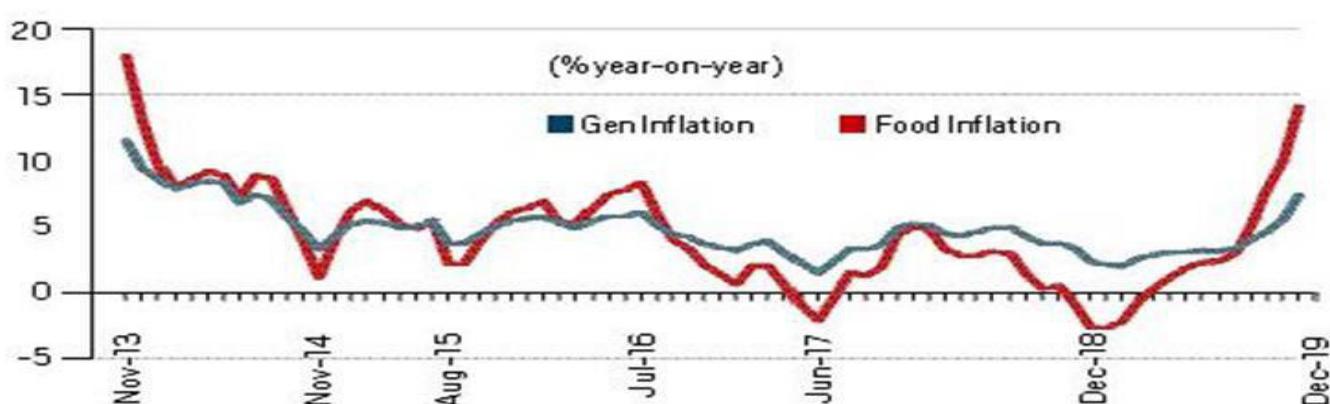
क्या अगले दो महीनों में सभी खाद्य पदार्थों की कीमतें समान रूप से घटेंगी?

संबिजियाँ जो ज्यादातर मौसमी और छोटी अवधि की फसलें हैं। के लिए संभावनाएँ अधिक हैं, किसान आम तौर पर एक सीजन में उत्पादन का विस्तार करके उच्च कीमतों पर प्रतिक्रिया देते हैं। हालाँकि, फसलों के मामले में यह स्थिति थोड़ी और मुश्किल हो सकती है, जहाँ तत्काल रूप से आपूर्ति बढ़ाई नहीं जा सकती है।

### थोक मूल्य सूचकांक (Wholesale Price Index)

- यह भारत में सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्रास्फीति संकेतक है।
- इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के आर्थिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
- इसमें घरेलू बाजार में थोक बिक्री के पहले बिंदु किए जाने-वाले सभी लेन-देन शामिल होते हैं।
- इस सूचकांक में कुछ चुनी हुई वस्तुओं को शामिल किया जाता है। इन वस्तुओं के औसत मूल्य में परिवर्तन के आधार पर महँगाई दर में परिवर्तन का पता चलता है।
- भारत और फिलीपींस जैसे देशों में महँगाई के माप के लिए थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है।
- वर्ष 2017 में अखिल भारतीय WPI के लिए आधार वर्ष 2004-05 से संशोधित कर 2011-12 को आधार वर्ष निश्चित किया गया है।
- भारत में इस सूचकांक में खाद्यान, धातु, इंधन और रसायन जैसे सभी पदार्थों को शामिल किया गया है, इससे महँगाई दर के बारे में सटीक जानकारी मिलने की सम्भावना अधिक रहती है।

## CONSUMER PRICE INFLATION: GENERAL VS FOOD



## HOW GLOBAL FOOD PRICES HAVE MOVED

COMMODITY	UNIT	CURRENT	YEARAGO	%CHANGE
Soyabean	USS/bushel	942.25	903.5	4.29
Corn	USS/bushel	389.5	378.5	2.91
Wheat	USS/bushel	562.25	514.25	9.33
Cocoa	USS/MT	2,583	2,341	10.34
Coffee	Cents/pound	114.55	102.75	11.48
Raw sugar	Cents/pound	14.16	12.75	11.06
Skimmed milk powder	USS/MT	3,026	2,201	37.48
Crude palm oil	USS/MT	760.73	517.63	46.96
Rice	USS/MT	450	410	9.76

इसका सबसे अच्छा उदाहरण दूध है, जहां किसानों ने 2015 से 2018 के लिए वास्तविक कम कीमत का अनुभव किया है।

जिसके कारण इनमें से कईयों ने धीरे-धीरे गायों के झुंड के आकार को कम कर दिया या दूध की पैदावार अधिक करने वाले पशुओं को अधिक चारा खिलाया। बेहतर कीमतें (महाराष्ट्र में डेरियाँ अब गाय का दूध 31-32 रुपये प्रति लीटर पर खरीद रही हैं, जबकि एक साल पहले यह 21-22 रुपये थी) मिलने के कारण किसानों द्वारा अधिक से अधिक जानवरों में निवेश करने की संभावना बढ़ जाती है और इससे गायों को भी बेहतर चारा मिलने लगता है। लेकिन इस तरह का परिणाम दिखने में समय लगेगा। हालाँकि, इसकी संभावना नहीं है कि दूध की कीमतें अगले कुछ महीनों में और बढ़ेंगी, खासकर गर्मियों के महीनों में, जब भैंसों और गायों द्वारा उत्पादन वैसे भी कम हो जाया करता है।

**क्या कुछ और ऐसा है जो मार्च के बाद भी खाद्य कीमतों में उछाल कायम रख सकता है?**

इस संदर्भ में देखने वाली बात वैश्विक कीमतें हैं। 2000 का दशक उच्च कृषि-कमोडिटी की कीमतों वाला रहा था। 2003 और 2011 के बीच, संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन (FAO) का विश्व खाद्य मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष: 2002-04 = 100) वार्षिक औसत 97.7 से 229.9 तक बढ़ गया था। हालाँकि, यह 2016 तक 161.5 तक सिमट गया था। भारत में सौम्य खाद्य कीमतों का प्रमुख कारण, उलटफेर के संकेत देने लगा है। 2019 में थां का बेंचमार्क इंडेक्स पिछले वर्ष की तुलना में 12.5% अधिक था। यह व्यक्तिगत खाद्य वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों (तालिका देखें) में एक सञ्च व्यवृत्ति में भी परिलक्षित होता है।

**सरकार क्या कर सकती है?**

खाद्य मुद्रास्फीति उन किसानों के लिए बुरी खबर नहीं है जो कम फसल की कीमतों और 2014 के बाद वैश्विक कमोडिटी में बढ़ोतरी की समाप्ति से पीड़ित हैं। एक कीमत रिकवरी से ग्रामीण आय को बढ़ावा मिलेगा, जो मौजूदा परिस्थितियों में खपत और समग्र आर्थिक विकास के लिए फायदेमंद है। लेकिन न तो सरकार और न ही आरबीआई खाद्य मुद्रास्फीति को अनदेखा कर सकती है, जो उपभोक्ताओं को नुकसान पहुँचा सकता है और ब्याज दर में और कटौती की संभावना को बढ़ा सकता है।

अब समय आ गया है कि सरकार अधिक से अधिक आयात की अनुमति देने के लिए दाल, दूध पाउडर, और खाद्य तेलों जैसी वस्तुओं को सामने लाये। सरकार को अंततः एक ऐसा निर्णय लेना होगा जो उत्पादकों और उपभोक्ताओं दोनों के हितों को संतुलित करता हो।

## CPI और WPI में अंतर

- थोक मूल्य सूचकांक (WPI) का उपयोग थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों का पता लगाने के लिए किया जाता है। अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापना या पता लगाना वास्तव में असंभव है। इसलिए थोक मूल्य सूचकांक में एक नमूने को लेकर मुद्रास्फीति को मापा जाता है। इसके पश्चात एक आधार वर्ष तय किया जाता है जिसके सापेक्ष में वर्तमान मुद्रास्फीति को मापा जाता है।
- भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर महँगाई की गणना की जाती है।
- उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) में मुद्रास्फीति की माप खुदरा स्तर पर की जाती है जिसमें उपभोक्ता प्रत्यक्ष रूप से जुड़े रहते हैं। यह पद्धति आम उपभोक्ता पर मुद्रास्फीति के प्रभाव को बेहतर तरीके से मापती है।
- WPI, आधारित मुद्रास्फीति की माप उत्पादक स्तर पर की जाती है जबकि और CPI के तहत उपभोक्ता स्तर पर कीमतों में परिवर्तन की माप की जाती है।
- दोनों बास्केट व्यापक अर्थव्यवस्था के भीतर मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति (मूल्य संकेतों की गति) को मापते हैं, दोनों सूचकांक अलग-अलग होते हैं जिसमें भोजन, ईंधन और निर्मित वस्तुओं का भारांक निर्धारित किया गया है।
- WPI सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को शामिल नहीं करता है, जबकि CPI में सेवाओं की कीमतों को शामिल किया जाता है।
- अप्रैल 2014 में, RBI ने मुद्रास्फीति के प्रमुख मापक के रूप में CPI को अपनाया था।

## उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (Consumer Food Price Index-CFPI)

- उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक को देश की आबादी द्वारा उपभोग किये गए खाद्य पदार्थों के खुदरा मूल्यों में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है।
  - इसके तहत ग्रामीण, शहरी और अखिल भारतीय आधार पर खाद्य मूल्य स्तर में आने वाले परिवर्तन की जानकारी दी जाती है।
  - इसका आधार वर्ष 2011-2012 है।

## संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )



## Expected Questions (Prelims Exams)

- 1. Consider the following statements:**

  1. Industrial Production Index is released by Central Statistics Office.
  2. Mostly wholesale price index is used as an inflation indicator in India.
  3. The Consumer Price Index is released on a quarterly basis.

Which of the above statements is/are correct?



नोट : 14 जनवरी को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा ( संभावित प्रश्न ) का उत्तर 1 (b) होगा।

## संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

- प्रश्न: ‘हाल ही में जारी वार्षिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की उच्च वृद्धि के आँकड़े ने भारतीय अर्थव्यवस्था के कमजोर होने के एक बड़े कारण को रेखांकित किया है।’ इन आँकड़ों का विश्लेषण भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्तमान स्वरूप के संदर्भ में करते हुए सरकार के द्वारा उठाए जा सकने वाले कदमों की भी चर्चा कीजिए। ( 250 शब्द )

**"The high inflation data in the recently released annual consumer price index has depicted a major reason for the weakening of the Indian economy." Analysing the data in the context of present form of Indian economy discuss the measures that could be taken by the Indian government.** (250 words)

**नोट :-** अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।